3 फरवरी, 2022 करेंट अफेयर्स

1. ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट: एलआईसी विश्व स्तर पर 10 वां सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड

- ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार, जीवन बीमा निगम को विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में 10वें स्थान पर रखा गया है।
- शीर्ष 10 की सूची में एलआईसी एकमात्र भारतीय बीमा कंपनी है।
- एलआईसी का मूल्यांकन 8.656 अरब डॉलर है। शीर्ष 10 में से, 5 चीनी बीमा कंपनियां हैं, पिंग एन इंश्योरेंस ब्रांड वैल्यू में 26 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद दुनिया के सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है।
- शीर्ष 10 में अमेरिका की दो कंपनियां हैं, जबकि फ्रांस, जर्मनी और भारत की एक-एक कंपनियां इस सूची में है।
- **एलआईसी अध्यक्ष:** एम आर कुमार
- **एलआईसी मुख्यालय:** मुंबई
- **एलआईसी की स्थापना:** 1 सितंबर 1956

2. आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक पद से इस्तीफा

- भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, उर्जित पटेल ने अगले महीने से शुरू होने वाले पूर्णकालिक कार्य का हवाला देते हुए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है।
- वह कंपनी के बोर्ड के सदस्य थे। पटेल को हाल ही में बीजिंग स्थित एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में दक्षिण एशिया में निवेश संचालन के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
- उनकी नियुक्ति एक फरवरी से प्रभावी है। आरबीआई के 24 वें गवर्नर के रूप में, पटेल ने रघुराम राजन का स्थान लिया था और 2016-2018 तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया था।
- इससे पहले, वह मौद्रिक नीति के प्रभारी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे।

3. एंटोनियो कोस्टा फिर बने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री

- पुर्तगाल के प्रधान मंत्री, एंटोनियो कोस्टा को उनकी केंद्र-वाम सोशलिस्ट पार्टी ने 2022 के पुर्तगाली विधायी चुनाव में शानदार जीत के बाद फिर से चुना गया है।
- सोशलिस्ट पार्टी को संसद की 230 सीटों में से 117 सीटें मिली हैं। कड़ी दौड़ की भविष्यवाणी के बावजूद, मुख्य विपक्षी केंद्र-दक्षिणपंथी PSD पार्टी को 27.8 प्रतिशत से 71 सीट मिली।
- एंटोनियो कोस्टा 26 नवंबर 2015 से पुर्तगाल के 119वें प्रधान मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।
- **पुर्तगाल के राष्ट्रपति:** मार्सेलो रेबेलो डी सोसा
- **पुर्तगाल राजधानी:** लिस्बन
- **पुर्तगाल मुद्रा:** यूरो

4. रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख होंगे लेफ्टिनेंट जनरल जीएवी रेड्डी

- लेफ्टिनेंट जनरल जीएवी रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी (Defence Intelligence Agency) का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है।
- जनरल रेड्डी लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों का स्थान लेंगे।
- लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों भारतीय सेना में अपने 39 साल के करियर के दौरान विभिन्न रणनीतिक पदों पर सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुए।

5. एक प्रबंधन पेशेवर आकाश कंसल द्वारा लिखित भारत की पहली सीज़न शैली की पुस्तक

- आकाश कंसल द्वारा लिखित भारत की पहली सीज़न शैली की पुस्तक जिसका शीर्षक द क्लास ऑफ़ 2006 स्नीक पीक इन द मिसएडवेंचर्स ऑफ़ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ़ है।
- पुस्तक को वस्तुतः IIT कानपुर, और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सबसे बड़े पुस्तक लॉन्च समारोहों में से एक में लॉन्च किया गया था।
- "2006 की कक्षा" में 18 अलग-अलग एपिसोड हैं जो कॉलेज में बिताए समय को याद करते हैं।
- पुस्तक का विमोचन अमेज़ॅन किंडल पर एक भारतीय फिल्म अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता आर. माधवन द्वारा किया गया था।

6. वित्त वर्ष 2022 में बैंक 50,000 करोड़ रुपये के 15 एनपीए खाते NARCL को हस्तांतरित करेंगे

- एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा के अनुसार, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या बैड बैंक और इंडियाडेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड परिचालन शुरू करने के लिए तैयार हैं।
- 82,845 करोड़ रुपये के कुल 38 गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (Non-Performing Asset - NPA) खातों को शुरू में NARCL में स्थानांतरित करने के लिए पहचाना गया है।

7. भारत सरकार ने की राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना

- आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, सरकार भूमि और अन्य गैर-प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (National Land Monetisation Corporation - NLMC) की स्थापना कर रही है।
- एनएलएमसी की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5000 करोड़ रुपये और सब्सक्राइब्ड शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपये होगी।
- अब तक, सीपीएसई ने एमटीएनएल, बीएसएनएल, बीपीसीएल, बीएंडआर, बीईएमएल, एचएमटी लिमिटेड, इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड सहित सीपीएसई से मुद्रीकरण के लिए 3,400 एकड़ भूमि और अन्य गैर-प्रमुख संपत्तियों को संदर्भित किया है।

8. बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए तीन दिवसीय मशाल रिले शुरू

- बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक मशाल रिले चीनी राजधानी में अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन के उद्घाटन से कुछ दिन पहले राजनयिक बहिष्कार और मेजबान शहर सहित चल रहे कोविड -19 के प्रकोप की पृष्ठभूमि के खिलाफ शुरू हुआ।
- बीजिंग 2022 आयोजन समिति ने कोरोनोवायरस महामारी के कारण रिले मार्ग को छोटा कर दिया था और मशाल उठाने वालों की संख्या भी घटाकर 1200 कर दी गई थी।

- पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल, 1924 का शीतकालीन ओलंपिक, फ्रांस के शैमॉनिक्स में आयोजित किया गया था।

9. अदालत की अवमानना

- भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण ने गुरुग्राम में जुमे की नमाज अदा करने वाले नमाजियों के प्रति 'सांप्रदायिक घृणा और आतंक का माहौल' बनाने वाले 'गुंडों' पर लगाम नहीं लगाने पर, हरियाणा सरकार के अधिकारियों के खिलाफ 'अवमानना कार्रवाई' शुरू करने की मांग करने वाली याचिका को सुनवाई के लिए तुरंत सूचीबद्ध करने पर सहमति प्रदान की है।
- शीर्ष अदालत में दायर याचिका में हरियाणा के अधिकारियों की निष्क्रियता को, वर्ष 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करने वाला बताते हुए निंदा की गयी है। अदालत ने अपने इस फैसले में कहा था, कि अधिकारियों को सांप्रदायिक हिंसा के मामले में मूक दर्शक नहीं रहना चाहिए और इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए तथा नफरत फैलाने वाले अपराधों के खिलाफ कानून का उपयोग करना चाहिए।
- यद्यपि 'अवमानना कानून' (Contempt Law) का मूल विचार उन लोगों को दंडित करना है जो अदालतों के आदेशों का सम्मान नहीं करते हैं। किंतु भारतीय संदर्भ में, अवमानना का उपयोग अदालत की गरिमा को कम करने तथा न्यायिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने वाली भाषा अथवा व्यक्तव्यों को दंडित करने के लिए भी किया जाता है।

- अदालत की अवमानना दो प्रकार की हो सकती है: सिविल अवमानना तथा आपराधिक अवमानना।

10. संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन

- 'हर घर, नल से जल' (Har Ghar, Nal Se Jal) योजना के तहत वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है।
- उद्देश्य: 2024 तक हर ग्रामीण घर में पाइप से पीने का पानी उपलब्ध कराना।
- यह सरकार के प्रमुख कार्यक्रम 'जल जीवन मिशन' का एक घटक है।
- यह योजना एक अनूठे मॉडल पर आधारित है। इसमें ग्रामीणों को शामिल करते हुए 'पानी समितियां' (water committee) गठित की जाती है, और ये समितियां ही यह तय करती हैं, कि अपने द्वारा उपभोग किए जाने वाले पानी के लिए ग्रामीण क्या भुगतान करेंगे।
- पानी समितियों द्वारा निर्धारित शुल्क, गांव के सभी निवासियों के लिए एक समान नहीं होगा। जिन ग्रामीणों के पास बड़े घर हैं, वे अधिक भुगतान करेंगे, जबकि गरीब परिवारों या जिन घरों में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है, उन्हें इस शुल्क से छूट दी जाएगी।
- 2018 में जारी की गयी नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, 600 मिलियन भारतीयों को पानी की कमी से अत्यधिक जूझना पड़ता है, और सुरक्षित जल तक अपर्याप्त पहुंच के कारण हर साल लगभग दो लाख व्यक्तियों की मौत हो जाती है।

- वर्ष 2030 तक, देश में पानी की मांग, उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी हो जाने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि करोड़ों लोगों के लिए पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ेगा और देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 6% की हानि होगी।
- अध्ययनों से यह भी पता चलता है, कि 84% ग्रामीण घरों में पाइप से आने वाले पानी की सुविधा नहीं है और देश का 70% से अधिक पानी दूषित है।